जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल, 04 अक्टूबर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. औषधियों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है.

दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इस मामले में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्पष्ट किया कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा. आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय औषधियाँ उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार सतर्क और सजग रहते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई कर रही है.

उन्होंने कहा कि 26 से 28 सितम्बर 2025 तक जिला छिंदवाड़ा में औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों एवं अस्पतालों का संयुक्त निरीक्षण किया गया. इस निरीक्षण में प्राप्त अनियमितताओं पर गंभीरता से संज्ञान लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इस दौरान कुल 19 औषधि नमूने संकलित कर शासकीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं.

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए 30 सितम्बर 2025 को छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ़ सिरप और नास्ट्रो-डीएस के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई.

30 सितम्बर 2025 को ही इंदौर स्थित आर्क फार्मास्यूटिकल्स के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर डिफ्रॉस्ट सिरप बैच नं. 11198 को बाजार से रिकॉल करने के निर्देश दिए गए. औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार), नई दिल्ली तथा संबंधित राज्यों हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के औषधि नियंत्रकों को 1 अक्टूबर 2025 को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया. साथ ही जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जिलों के औषधि निरीक्षकों को सम्मिलित कर 1 अक्टूबर 2025 को विशेष जांच दल गठित किया गया.

समस्त औषधि निर्माताओं, औषधि निरीक्षकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा मेडिकल कॉलेजों के डीन को 1 अक्टूबर 2025 को क्लोर फ़ेनिरामाइन मलेट एवं फ़ेनाइलफ़्रिन एचसीएल के उपयोग के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है. जबलपुर स्थित कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर कार्रवाई करते हुए 2 अक्टूबर 2025 को कोल्ड्रिफ सिरप की 66 बोतलों में से 50 बोतलें बिक्री हेतु रोक दी गई और 16 बोतलों का नमूना परीक्षण के लिए संकलित किया गया है.

तमिलनाडु औषधि नियंत्रक कार्यालय से कोल्ड्रिफ सिरप(बैच नं. एसआर-13, स्र्द्धद्द. ष्ह्ल. 05/2025) को अवमानक घोषित किए जाने की सूचना 4 अक्टूबर को प्राप्त हुई. इस सूचना के आधार पर मध्यप्रदेश में इसके विक्रय और वितरण पर 4 अक्टूबर को तत्काल रोक लगा दी गई है. साथ ही उक्त निर्माता फर्म के अन्य सभी उत्पादों पर भी 4 अक्टूबर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा और जबलपुर को इस प्रकरण में आगामी कठोर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है.

मृत बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराना गंभीर लापरवाही : नायक

विशेष संवाददाता

भोपाल, 04 अक्टूबर. मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने शनिवार को भाजपा सरकार पर कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के मामले में जिम्मेदारों को बचाने का आरोप लगाया.

नायक ने कहा कि मृत बच्चों का पोस्टमार्टम न कराना सरकार की गंभीर लापरवाही और कुतरर्कपूर्ण चुप्पी को दर्शाता है. उन्होंने आशंका जताई कि यह कदम दवा कंपनी को बचाने के लिए उठाया गया है. नायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यदि निर्दोष है तो जांच से क्यों डर रही है. उन्होंने मृतक बच्चों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी जांच की मांग की और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया. कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा.

बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? : उमंग

घटिया कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत पर भाजपा सरकार को घेरा

भोपाल, 4 अक्टूबर. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड में कथित तौर पर घटिया कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र और दवा वितरण प्रणाली की पोल खोल दी है.

कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार

जांच में देरी ने बढ़ाया मौतों का सिलसिला

प्रोटोकॉल के अनुसार दवा सैंपल की जांच 72 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन 29 सितंबर को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने में 6 दिन लग गए. इस देरी ने कई बच्चों की जान ले ली. इस बीच उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया कि कफ सिरप से मौतें नहीं हुईं, यह अफवाह है. सिंघार ने आरोप लगाया कि मंत्री ने तीन सिरपों के शुरुआती टेस्ट क्लीन आने के बाद कंपनी को क्लीन चिट दे दी, जबकि 12 सिरपों के सैंपल की जांच लंबित थी.

ने इस मामले को लेकर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सिंघार ने कहा कि यह त्रासदी एक भ्रष्ट और लापरवाह सिस्टम का परिणाम है. आज प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि कहीं चूहे मरीजों को काट रहे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, और जो दवाएं मिलती हैं, वे या तो अमानक हैं या नकली.

सीएजी रिपोर्ट और विधानसभा के तथ्य भी चिंताजनक नवंबर 2024 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, छिंदवाड़ा और ग्वालियर सहित कई जिलों में 11 करोड़ से अधिक की 263 दवाएं एक्सपायर हो गईं.

बच्चों की मौत का आंकड़ा 11 पहुंचा

- मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4 लाख की आर्थिक सहायता
- दर्जनों मौतों के बाद भी कारणों पर नहीं पहुंच पाया प्रशासन

छिंदवाड़ा/परासिया. परासिया तहसील में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है. बीते एक माह में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है.

ताजा मामला बड़कुही की 3 वर्षीय योगिता धरसे का है, जिसकी मौत नागपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई. स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 9 बच्चों के नाम दर्ज हैं, जबकि डुड्डी गांव के 7 वर्षीय दिव्यांश चंद्रवंशी और परासिया वार्ड क्रमांक 9 की 18 माह की श्रेया यादव का नाम सूची में नहीं है.

मृतकों में खजूरिया की संध्या (14 माह), अदनान खान (5 वर्ष), हेतांश सोनी (5 वर्ष), उसैद (4 वर्ष), शिवम राठौर (4 वर्ष), विधि, रिषिका पिपरे (5 वर्ष), चंचलेश और विकास यदुवंशी (4 वर्ष) शामिल हैं. शनिवार रात मृतक योगिता का शव परिजन बड़कुही लेकर पहुंचे. भोपाल, बालाघाट और छिंदवाड़ा की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात परासिया में तीन मेडिकल दुकानों पर छापामार कार्रवाई की. जांच में शासन द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बड़ी मात्रा में बरामद किए गए.

छिंदवाड़ा त्रासदी पर कांग्रेस नेता का अनोखा विरोध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 04 अक्टूबर. छिंदवाड़ा में ग्यारह बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बलोरिया ने शनिवार को प्रदेश सरकार और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर सीधा हमला बोला.

बलोरिया ने राजधानी भोपाल में मीडिया के सामने शुक्ल का फोटो रखकर उस पर खांसी की दवा उड़ेलते हुए विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि यह कदम जनता के गुस्से और सरकार की लापरवाही का प्रतीक है.

बलोरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही और सरकार की उदासीनता के कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुई. उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों की जान जाने जैसी गंभीर घटना सरकार की नाक के नीचे कैसे घट सकती है. कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही मृतकों के परिवारों को तात्कालिक राहत और उचित मुआवजा देने की अपील की है.

- कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई की होती तो यह हादसा रोका जा सकता था.

पत्थर की 10 मूर्तियां तैयार, 200 प्रतिमाएं बना रहे हैं कलाकार

- महाकाल लोक में बदली जाएगी एफआरपी प्रतिमाएं
- आंधी तूफान में टूटी सप्त ऋषियो की प्रतिमाओं के बाद चल रहा नए सिरे से काम
- हरि फ़ाटक मार्ग स्थित नीलगंगा हाट बाजार में तराशी जा रही मूर्तियां

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषि की प्रतिमाएं आंधी तूफान में उखड़ गई थी. उसके बाद सभी मूर्तियों को एफआरपी की बजाय पत्थर की लगाने का निर्णय लिया गया, 200 मूर्तियों को बनाने का काम जो चल रहा है उसमें अभी 10 मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी है. उड़ीसा से आए कलाकार इन मूर्तियों को तराशने का काम कर रहे हैं.

दरअसल महाकाल लोक में लगी (फाइबर रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक) की मूर्तियों को अब पत्थर की मूर्तियों से बदला जा रहा है. तूफ़ान में टूटी मूर्तियों के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर यह निर्णय लिया गया था. मूर्ति बनवाने और लगाने का जिम्मा अब संस्कृति विभाग के पास है.

पहाड़पुर से आया पत्थर

ओडिशा के कलाकार बंशी ने नवभारत को बताया कि पहाड़पुर के पत्थर से ये मूर्तियां तराश रहे हैं. इस बदलाव से न केवल मूर्तियों की भव्यता और टिकाऊपन बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में आंधी तूफान का भी असर पत्थर की प्रतिमाओं पर नहीं होगा.

एफआरपी की मूर्तियों की उम्र 10 साल

कलाकारों ने मूर्ति तराशने के दौरान यह भी बताया कि एफआरपी की मूर्तियों की उम्र लगभग 10 साल ही होती है, जबकि पत्थर की मूर्तियां लंबे समय तक चलती हैं. हालांकि यह बात अलग है कि जब एफआरपी की प्रतिमाएं महाकाल लोक में लगाई गई थी तब उनकी उम्र 100 साल बताई गई थी, आंधी तूफान में मूर्ति गिरने के बाद उनकी उम्र 90 साल कम कैसे हो गई यह कोई जिम्मेदार नहीं बता पा रहा.

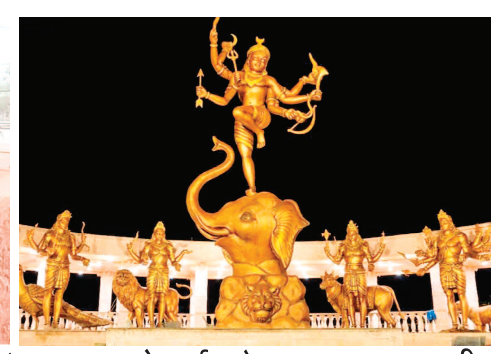

लोकार्पण के 1 साल बाद उखड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था. 2023 के तूफ़ान में महाकाल लोक की कई मूर्तियां टूटकर गिर गईं थीं, जिससे ये नुकसान हुआ और दोबारा पत्थर की मूर्तियों की आवश्यकता पड़ी. 1 साल में ही सप्त ऋषि की मूर्तियां उखड़ कर परिसर में फैल गई थी, जिसके बाद देश भर में यह मामला सुर्खियों में आया.

गुणवत्ता और सम्मान

अब यह भी एक कारण सामने आया कि धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक की मूर्तियां न लगाने की जाए, इसलिए अब पत्थर की मूर्तियां लगाई जा रही हैं. पत्थरों में गुणवत्ता भी होती है और धार्मिक दृष्टि से उनका सम्मान भी होता है जबकि प्लास्टिक की मूर्तियां ना लगे इसके लिए कई लोगों ने मांग भी उठाई थी.

एक मूर्ति की कीमत 25 से 30 लाख

ओडिशा के कलाकार पहाड़पुर के पत्थर से मूर्तियां बना रहे हैं. ओडिशा के कलाकारों को मूर्तिकला में विशेषज्ञता हासिल है. एक पत्थर की मूर्ति बनाने में लगभग 25 से 30 लाख रुपये तक का खर्च आ रहा है.

इनका कहना

कुल 200 मूर्तियां बनाई जाना है, लगभग एक दर्जन मूर्तियां अब तक बन चुकी है, मूर्तियों का यह कार्य संस्कृति विभाग के जिम्मे है. हम भी इस संबंध में अवलोकन करेंगे की मूर्तियों का कार्य कहां तक पहुंचा है. मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रतिमाएं जल्द बनाकर तैयार हो और स्थापित हो जाए.

- प्रथम कौशिक, महाकाल मंदिर प्रशासक

कुल मूर्तियों की संख्या

महाकाल लोक में लगभग 200 मूर्तियां हैं, सप्त ऋषियों के साथ ही बाकी सभी मूर्तियां भी बदली जाएगी. हालांकि कार्य धीमी गति से चल रहा है और अभी तक 10 मूर्तियां ही बन पाई है बाकी मूर्तियां कब तक बनेगी और कब लगेगी इसके बारे में अभी किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई.

वीआईटी में 18 छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधियां

वीआईटी विवि का छठवां दीक्षांत समारोह आयोजित

भोपाल, 4 अक्टूबर. वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय में शनिवार को छठवां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. इसमें 2572 स्नातक, 503 स्नातकोत्तर और 18 डॉक्टरेट छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की गईं. समारोह की अध्यक्षता चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन ने की.

मुख्य अतिथि के रूप में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि संस्कृति और विज्ञान, दोनों ही मानव प्रगति के दो आधार हैं. विज्ञान तकनीक देता है, संस्कृति मूल्य और दिशा. उन्होंने भारतीय गुरुकुल परंपरा को समग्र शिक्षा का प्रतीक बताया, जहाँ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन था. डॉ. जोशी ने कहा कि योग, ध्यान और शास्त्रीय कलाएँ व्यक्ति को आत्मबल और संतुलन देती हैं.

उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे मूल्यों को समाज की नैतिक नींव बताया. भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं—भक्ति आंदोलन, केरल की मार्शल आर्ट्स और पूर्वोत्तर की बुनाई कला—का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हमारी विरासत सीमाएँ नहीं, शक्ति का स्रोत है.

गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए एमपी ट्रांसको का बड़ा कदम

- इंदौर के 12 सबस्टेशनों सहित प्रदेश के 412 सब स्टेशनों में कैपेसिटर बैंक स्थापित

इंदौर. उपभोक्ताओं को मानक वोल्टेज पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की दिशा में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.

एम पी ट्रांसको के प्रदेश के अपने 417 सबस्टेशनों में से 412 पर विभिन्न क्षमताओं के कैपेसिटर बैंक संचालित है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एमपी ट्रांसको की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि कैपेसिटर बैंकों की व्यवस्था से प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता और स्थिर वोल्टेज पर बिजली आपूर्ति संभव हो रही है.

इंदौर मे 441 एमव्हीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा इंदौर में विद्युत ट्रांसमिशन 400 के.वी., 220 के.वी. एवं 132 के.वी. के सबस्टेशनों द्वारा किया जाता है. इनमें एक 400 के.वी. सबस्टेशन, चार 220 के.वी. सबस्टेशन-साउथ ज़ोन, इंदौर ईस्ट बिचौली, मंगलिया और देपालपुर ङ्क तथा सात 132 के.वी. सबस्टेशन- राऊ, सत्यसाई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, निरंजनपुर, महालक्ष्मी नगर जी.आई.एस., इंदौर वेस्ट (चंबल) और नवदापंथ शामिल हैं. उपभोक्ताओं को मानक वोल्टेज स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इन सबस्टेशनों पर कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं.

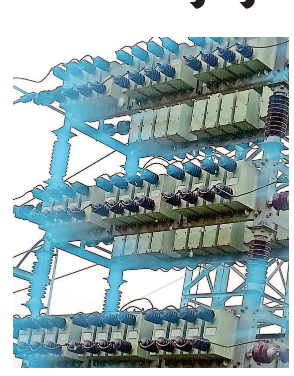

प्रदेश में कुल 751 कैपेसिटर बैंक

प्रदेश स्तर पर एमपी ट्रांसको के कुल 751 कैपेसिटर बैंक सक्रिय हैं. इनमें 220 केवी सबस्टेशनों पर 145 केवी स्तर के 32 कैपेसिटर बैंक तथा 132 केवी सबस्टेशनों पर 36 केवी स्तर के 719 कैपेसिटर बैंक शामिल हैं. इनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 9278.5 एम.व्ही.ए.आर. है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

इंदौर के इन सबस्टेशनों पर लगे हैं पेसिटर बैंक

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता अमर कीर्ति सक्सेना में बताया कि इंदौर में 132 के.वी. चंबल एवं 220 के.वी. नॉर्थ ज़ोन सबस्टेशन पर 48-48 एम.व्ही.ए.आर., सत्यसाई एवं जैतपुरा सबस्टेशन पर 12-12 एम.व्ही.ए.आर., 220 के.वी. बिचौली पर 24 एम.व्ही.ए.आर., इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, महालक्ष्मी नगर और निरंजनपुर सबस्टेशन पर 12-12 एम.व्ही.ए.आर., 220 के.वी. देपालपुर पर 36 एम.व्ही.ए.आर., 220 के.वी. साउथ ज़ोन इंदौर पर 48 एम.व्ही.ए.आर., 132 के.वी. राऊ पर 24 एम.व्ही.ए.आर. (सभी 36 के.वी. वोल्टेज स्तर पर) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 220 के.वी. सबस्टेशन इंदौर जैतपुरा-दो पर 145 के.वी. वोल्टेज स्तर पर 33 एम.व्ही.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं. इंदौर स्थित 12 एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशनों पर कुल 441 एम.व्ही.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं.

दीक्षांत समारोह | राष्ट्रीय मेरिट में नाम दर्ज कर जिले व प्रदेश का बढ़ाया गौरव

प्रधानमंत्री ने बैतूल की छात्रा त्रिशा को किया सम्मानित

नई दिल्ली/ बैतूल,04 अक्टूबर. मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई की छात्रा कु. त्रिशा तावड़े ने सेंट्रल जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में त्रिशा को सम्मानित किया. प्रधानमंत्री ने इस दौरान पीएम सेतु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई) सहित युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया.

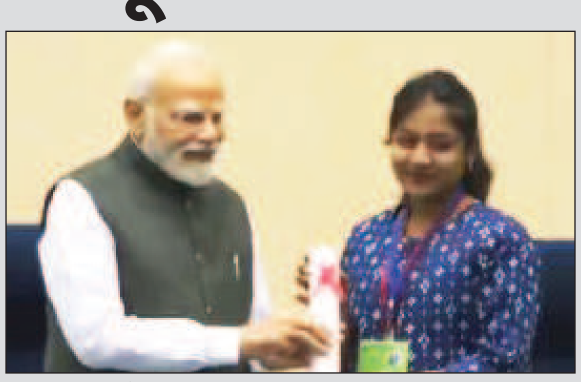

कु. त्रिशा ने 1200 में से 1187 अंक प्राप्त कर प्रदेश की एकमात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में मेरिट में स्थान पाया है. वह बैतूल जिले के ग्राम भड़ूस की निवासी हैं. उनके पिता अजय तावड़े बस ड्राइवर हैं और माता सुशीला तावड़े गृहणी हैं. बड़ी बहन कु. एकता तावड़े भी एकलव्य महिला आईटीआई की टॉपर रह चुकी हैं और वर्तमान में रेलवे में एप्रेंटिश कर रही हैं.

हुनर पहल के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप प्रदेश की आईटीआई संस्थाओं में छात्राओं के कौशल विकास और उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. बैतूल की महिला आईटीआई में हुनर पहल के तहत छात्राओं को 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल, हार्टफुलनेस ध्यान प्रशिक्षण और योग व कराटे प्रशिक्षण शामिल हैं. इसके अलावा, वाधवानी फाउंडेशन के साथ एमओयू के तहत व्यक्तित्व विकास एवं जीवन तरंग कक्षा आयोजित की जा रही है. ड्यूलिंगो एप के माध्यम से छात्राओं को जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि उन्हें देश ही नहीं, विदेश में भी रोजगार के अवसर मिल सकें. प्रोजेक्ट कोड पहल के अंतर्गत रवि कोड योगी के माध्यम से कोडिंग-डिकोडिंग प्रशिक्षण भी संचालित है.

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाएगी सरकार

सभाओं ने 4 हजार से अधिक विलेज एक्शन प्लान का किया अनुमोदन

भोपाल,4 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल जिलों की ग्राम सभाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि आदि सेवा पर्व के अवसर पर दो अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं ने आपसी विचार-विमर्श कर 4 हजार से अधिक विलेज एक्शन प्लान का अनुमोदन किया है. शेष ग्राम सभाएं भी जल्द ही अपने एक्शन प्लान तैयार करेंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं को विकास का स्वयं का रोडमैप तैयार करने की शक्ति दे रही है. इस दिशा में 30 जनजातीय बहुल जिलों के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने गांवों में जाकर ग्रामीणों को आदि कर्मयोगी अभियान और आदि सेवा पर्व का महत्व समझाया.

सेवा केंद्र होंगे गांवों के 'एकल खिड़की सेवा केंद्र'

विशेष ग्राम सभाओं में निर्णय लिया गया कि हर गांव में एक आदि सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो स्थानीय नागरिकों के लिए एकल खिड़की सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगा. इन केंद्रों पर ग्रामीण सप्ताह में एक घंटा आदि सेवा समय卐 के रूप में स्वैच्छिक श्रमदान करेंगे. इसके साथ ही, अधिकारियों और स्थानीय नेतृत्व को जनजातीय समुदाय की भाषा, बोली और संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है. ग्राम सभाओं ने जनजाति ग्राम विजन 2030 के लिए अपने विशेष एक्शन प्लान को भी अनुमोदित किया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60